आकाशवाणी केन्द्र शिमला
11.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- आरडीजी के मुद्दे पर राज्य सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक– प्रदेश के आर्थिक हालात पर होगी चर्चा।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आरडीजी को बताया प्रदेश का संवैधानिक अधिकार।
- प्रदेश भाजपा ने मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार– फिजूलखर्ची को बढ़ावा देने का लगाया आरोप।
- सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल में बीएसएनएल सेवाओं को मजबूत करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया–स्टॉफ की भारी कमी दूर करने का किया आग्रह।

मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने आर.डी.जी. के मुद्दे पर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली से लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस बैठक में आर.डी.जी. बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वित्तीय घाटे के बावजूद राज्य सरकार न तो नौकरियां खत्म करेगी और न ही पुरानी पैंशन योजना बंद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान संवैधानिक अधिकार है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।

कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हम जनता को यह जागरूक करना चाहते है कि ये अधिकार है जनता का। सरकार आती है सरकार जाती है। मुख्यमंत्री आते हैं,मुख्यमंत्री जाते हैं लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए। रोज मेरे खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करके और सोशल मीडिया पर टीम लगाकर मुझे गाली देने से नहीं होगा ,प्रदेश का हिट तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाकर देश के प्रधानमंत्री से सभी सांसदों को लेकर मिलेंगे और कहेंगे कि ये छोटी प्रदेशों। का अधिकार है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको खत्म करना प्रदेश के हित में नहीं है। जो 1952 में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही है और 73 साल बाद उसको खत्म करना अच्छी बात नहीं है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान संसद सत्र के चलते वे जेपी नड्डा सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर पाए। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर आर.डी.जी. सहित संगठन के मुद्दों पर चर्चा की है।

पी चिदंबरम जी ने कहा कि आरडीजी संविधान के आर्टिकल 271(5) द्वारा दिया गया एक अधिकार है। और इसमें हिल स्टेट और छोटे स्टेटस का मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं, हमेशा ख्याल रखा जाता रहा है और उन बड़े राज्यों का भी ख्याल रखा जाता है जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो घाटा होता है उनका भी ख्याल रखा जाता है। हैरानी की बात है कि आरडीजी जो संविधान के अधिकार द्वारा दी गई है उसे सारा राज्यों के नाम पर बंद कर दिया गया तो उन्होंने हमारी बात को सुना भी और आरडीजी के मामले में हमें और आने

वाले समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे सुझाव देने का भी कहा आने वाले समय में बात नड्डा जी से भी इस बारे में बात करूंगा।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य की मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला में आज पत्रकारा वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए और लगातार फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से सीपीएस लगाए और सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की पैरवी करने के लिए वकीलों को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगमों व बोर्डों में बड़ी संख्या में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तैनात किए गए हैं और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बिंदल ने कहा कि आरडीजी बंद होने से नहीं राज्य सरकार के कुप्रबंधन से ही प्रदेश आज आर्थिक बदहाली की दहलीज पर पहुंच गया है।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल में दूरसंचार सेवाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बी.एस.एन.एल. नेटवर्क की समस्या है और निगम में स्टॉफ की भी भारी कमी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्टॉफ की कमी के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क रखरखाव और सेवा बहाली में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष कनेक्टिविटी योजनाएं चलाई जा रही है और फुल सेचुरेशन योजना के तहत देश के लगभग 3 हजार गांव चिन्हित किए गए हैं जहां 21 हजार टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शतप्रतिशत कनेक्टिविटी के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाएगा।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्ज के सहारे चल रही है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ही सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है। कुल्लू में आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित समर्पण दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है जबकि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए सैंकड़ों संस्थान बंद कर दिए हैं।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और नागरिकों का बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। उन्होंने आज राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने आईजीएमसी शिमला में 17 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए साढ़े 14 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से सहायता प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एन.एच.एम., आयुष्मान भारत, गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हिमाचल को केंद्र द्वारा समुचित धनराशि जारी की गई है।